इकाई 15 आर्थिक संबंध

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 परिचय

15.2 भारत का आर्थिक परिदृश्य

15.3 अर्थव्यवस्थाः आजादी के बाद

15.4 भारत और विश्व व्यापार संगठन

15.5 भारत बनाम आसियान

15.6 भारत और जी20

15.7 दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार संबंध

15.8 व्यापार और विदेश नीति

15.9 2030 तक भारत

15.10 सारांश

15.11 कुछ उपयोगी सन्दर्भ

15.12 आपके प्रगति अभ्यासों की जांच के लिए उत्तर

15.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप भारत के प्रमुख आर्थिक सरोकारों के बारे में पढ़ेंगे । इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य होंगे कि

- भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास की अनिवार्यता को समझें;
- उदारीकरण से पहले और बाद के युग (1991 से पहले और बाद) में भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन के तरीके को समझें और उनमें अंतर करें;
- क्षेत्र और विश्व स्तर पर, विदेश और व्यापार संबंधों पर इसका परिणामी प्रभाव; तथा
- भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और कमजोरियों और भारत को प्रभावित करने वाले वैश्विक प्रतिमानों की व्याख्या करें।

15.1 परिचय

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है – 2.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपने स्थिर संचालन को जारी रखने के लिए तैयार है। भारत की आर्थिक नीति का एक उद्देश्य अपने बाजारों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना, आयात को कम करना और निर्यात को प्रोत्साहित करना रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में भारत में निवेश को आकर्षित करना और

विदेशी विनिर्माण उद्योग को भारतीय परिचालन स्थापित करने की सुविधा देना दूसरी बात है। 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 'मेक इन इंडिया' अभियान एक ओर अर्थव्यवस्था को विकसित करने और दूसरी ओर रोजगार पैदा करने में मदद करने के लिए निवेश आमंत्रित करने के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इसका एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण वैश्विक बाजारों में भारत के आर्थिक सहयोग में बदलाव है।

भले ही भारत ने 2018 में वस्तुओं और सेवाओं में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का उत्पादन किया, लेकिन शीर्ष तीन चीन, 24 ट्रिलियन डॉलर के उत्पादन के साथय यूरोपीय संघ (ईयू) 20 ट्रिलियन डॉलर के साथय और, यूएस 18 ट्रिलियन डॉलर के साथ को पीछे छोड़ने में थोड़ा समय लगेगाः । भारत अब 2030 तक लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य बना रहा है। प्रधान मंत्री मोदी के तहत दूसरे कार्यकाल के लिए नव निर्वाचित सरकार ने वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर बनने का लक्ष्य रखा है। एक वैश्वीकृत दुनिया में, भारत, 2008–14 के दौरान 5–11 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई और उसके बाद 4–8 प्रतिशत के बीच थोड़ी धीमी रही। भारत एक बाजार अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित हो गया है, कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण कर दिया है, निजी क्षेत्र और एफडीआई के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और कई उद्योगों को नियंत्रित किया है। कहने की जरूरत नहीं है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनकर भारत को व्यापार से संबंधित कई चिंताओं का सामना करना पड़ा–द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, प्रतिबंध, डंपिंग और वार्ता–वैश्विक और क्षेत्रीय, गैट से विश्व व्यापार संगठन तक। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस अभूतपूर्व वृद्धि ने दस करोड़ से अधिक भारतीयों को घोर गरीबी से बाहर निकाला है। भारत के तीव्र आर्थिक विकास ने पिछले दो दशकों के दौरान अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है – इतना अधिक कि आज यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

15.2 भारत का आर्थिक परिदृश्य

2017–18 में भारत की जीडीपी 7.2 प्रतिशत और 2018–19 में 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। भारत ने 4,750 से अधिक प्रौद्योगिकी स्टार्ट–अप के साथ दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्ट–अप बेस के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। जनसंख्या वृद्धि दर, श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि और उच्च शिक्षा नामांकन, अन्य कारकों के आधार पर, 2020 तक भारत की श्रम शक्ति के 160–170 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, मार्च 2019 तक सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 405.64 बिलियन डॉलर था।

2018–19 (फरवरी 2019 तक) के दौरान, भारत से माल का निर्यात सालाना आधार पर 8.85 प्रतिशत बढ़कर 298.47 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि सेवा निर्यात सालाना आधार पर 8.54 प्रतिशत बढ़कर 185.51 बिलियन डॉलर हो गया है। सेवाओं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, निर्माण, व्यापार और ऑटोमोबाइल से अधिकतम योगदान के साथ, अप्रैल 2000 और दिसंबर 2018 के बीच भारत का एफडीआई इक्विटी प्रवाह 409.15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

भारत विरोधाभासों का देश है, जो गहन और पुरानी चुनौतियों के साथ विशाल संभावनाओं से जूझ रहा है। 1980 के दशक तक भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बंद थी। हाल

के दशकों में, नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला ने धीरे–धीरे इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया है निर्यात और आयात दोनों बढ़े हैं। इसकी हाल की उच्च आर्थिक विकास दर ने संभावनाओं में सुधार किया है कि दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश अपने 1.3 अरब लोगों के लिए व्यापक रूप से आय बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान करने में सक्षम होगा।

फिर भी, भारत दुनिया में गरीबी का सबसे बड़ा पूल बना हुआ है – लगभग 300 मिलियन – और राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार, 800 मिलियन से अधिक लोग प्रतिदिन 2 डॉलर से कम पर जीवित हैं। लगभग दो–तिहाई भारतीय अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है, जहां पिछले दशक के दौरान विकास 3 प्रतिशत से भी कम रहा है। इसके विपरीत, भारत का विश्व–प्रसिद्ध उच्च–प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र हाल के वर्षों में मजबूती से विकसित हुआ है, लेकिन अभी भी 1 प्रतिशत से भी कम कर्मचारियों को रोजगार देता है।

दुनिया के साथ भारत के व्यापार के हालिया विस्तार के बावजूद, वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा अपने आकार को देखते हुए अनुपातिक रूप से छोटा है। भारत के बाध्य टैरिफ अभी भी अपेक्षाकृत अधिक हैं, हालांकि लागू टैरिफ बहुत कम हैं। इस अंतर के कारण, सरकार वर्तमान में व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत स्थान बरकरार रखती है, जिसमें मौजूदा परिस्थितियों के जवाब में टैरिफ बढ़ाने और कम करने की क्षमता शामिल है। इस प्रकार, व्यापार वार्ता में निचले स्तरों पर टैरिफ को बाध्य करने या अन्यथा अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ अपने जुड़ाव को नियंत्रित करने वाले नियमों को बदलने के लिए इसके मौजूदा नीति स्थान को बाधित करता है और संभावित रूप से अर्थव्यवस्था के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

भारत के आर्थिक उदारीकरण की नीति को 1991 से लागू किया गया था। आर्थिक उदारीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू विदेशी व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण है। भारत तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो रहा है और अपनी व्यापार समायोजन को उदार बना रहा है। उदाहरण के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार 1990 में 15.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 39.8 प्रतिशत हो गया है – ऑस्ट्रेलिया के समान स्तर के आसपास – और 2016 में भारत का साधारण औसत सबसे पसंदीदा राष्ट्र लागू टैरिफ 1990–91 में यह जो था का एक–दसवां था ।

15.3 अर्थव्यवस्थाः आजादी के बाद

स्वतंत्रता से लेकर 1980 के दशक तक नियोजित विनियमन और आयात प्रतिस्थापन की सामान्य नीति थी। 1980 के दशक के बाद, सरकार ने उदारीकरण के कुछ आंशिक स्वरूप पर ध्यान देना शुरू किया और फिर 1991 के बाद चरण आया, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित था।

1947–52 के पहले चरण के दौरान, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत का भुगतान संतुलन डॉलर की तुलना में प्रतिकूल था, विदेशी मुद्रा लाने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए एक खाका तैयार किया गया था। इसके लिए भारत को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1949 में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा। इस दौरान आयात नीति रक्षा थी और घरेलू कमियों के कारण सीमाएं लगाई गईं। स्टर्लिंग बैलेंस के उपयोग पर यूके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों

के कारण भारत भी आयात को उदार नहीं बना सका, जो युद्ध नियंत्रण की अवधि की विरासत थी।

दूसरा चरण, जो 1957 तक चला, सरकार ने तेजी से उदारीकृत व्यापार नीति अपनाई। आयात लाइसेंस दिए गए और आयात नियंत्रणों को उदार बनाकर निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। 1958 से 1975 तक तीसरे चरण के दौरान, मुदलियार समिति (1962) सहित व्यापार नीति की व्यापक समीक्षा की गई। 1966 में एक बार फिर रुपये का अवमूल्यन किया गया और व्यापार नीति ने निर्यात को विकसित करने और आयात को अत्यधिक उदार बनाने का प्रयास किया।

अंतिम चरण (1975 से आगे) के दौरान सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात उदारीकरण की नीति अपनाई। जनता पार्टी सरकार (1977–79) के दौरान आयात उदारीकरण को भी अपनाया गया ताकि मूल्य स्तर में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि की जा सके और आयात उदारीकरण के माध्यम से आर्थिक विस्तार और निर्यात को बढ़ावा देने का इरादा किया जा सके। आयात–निर्यात नीति (1985) का निर्धारण आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों पर आधारित था।

1991 में प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण का पहला बड़ा प्रयास वास्तव में 1984 में सत्ता में आने के बाद प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 1985 की प्रारंभिक उदारीकरण प्रक्रिया ने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में नीतिगत परिवर्तनों का प्रयास किया जैसे, औद्योगिक, व्यापार, राजकोषीय और मौद्रिक। परिणामस्वरूप, 1985–90 के दौरान, निर्यात में डॉलर के संदर्भ में 17 प्रतिशत से अधिक की रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि देखी गई।

नियामक प्रक्रियाओं की सीमाओं को महसूस करते हुए, सरकार ने 1991 में कई उपायों की घोषणा की। उदारीकरण की शुरुआत प्रतिबंधों को कम करने और अर्थव्यवस्था के संबंधित क्षेत्रों को खोलने के लिए की गई थी नियंत्रण में आसानी और, लाइसेंस–निरीक्षक–राज की समाप्ति। फोकस के क्षेत्रों में शामिल हैंः औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात–आयात नीति, प्रौद्योगिकी उन्नयन, राजकोषीय नीति और विदेशी निवेश। भारत के लिए वैश्विक मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के उद्देश्य से सुधार विस्तृत और व्यापक थे।

उपायों में शामिल हैं, शुल्क छूट योजना; निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) की स्थापना; विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ); निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (EPCG) योजना; एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस और स्टार ट्रेडिंग हाउस; निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं; सोने के आयात का उदारीकरण; भारत की विदेशी निवेश नीति; विनिमय दर उदारीकरणय आंशिक रुपया परिवर्तनीयता; व्यापार खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता; पूंजी खाता परिवर्तनीयता; और, निर्यात–आयात नीति और निर्यात–आयात बैंक में सुधार।

बोध प्रश्न 1

1. स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति की व्याख्या करें?

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पूर्व के चरणों की व्याख्या करें।

.....

.....

15.4 भारत और विश्व व्यापार संगठन

टैरिफ और व्यापार (GATT) 1986–93 पर सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) को जन्म दिया। टैरिफ और व्यापार का गठन जिनेवा, 1948 में सदस्य देशों के विकास और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मुक्त व्यापार की सुविधा के लिए किया गया था। 1 जनवरी 1995 को, टैरिफ और व्यापार को मराकेरा समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में संपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्व रखता है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का कानूनी संस्थान बन गया, जो भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार के मुद्दों के नियमन से संबंधित है। भारत टैरिफ और व्यापार और विश्व व्यापार संगठन दोनों का संस्थापक सदस्य रहा है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद, भारत की व्यापार नीतियां विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों और नीति निर्देशों के अनुसार नाटकीय रूप से बदल गईं।

विश्व व्यापार संगठन के तहत भारत को कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्न हैं: विदेशी व्यापार में वृद्धि कृषि निर्यात में वृद्धि विदेशी पूंजी निवेश की आमद और, सेवाओं में निवेश। इसके नुकसान भी थे, उदाहरण के लिए, घरेलू उद्योगों की हानि; घरेलू कीमतों पर प्रभाव रोजगार पर प्रभाव; सार्क, आसियान आदि जैसे क्षेत्रीय समूहों में गिरावट।

विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व के दौरान इस बात पर बहस छिड़ गई है कि भारत ने इससे क्या हासिल किया है। यह एक विवाद निपटान निकाय बन गया है और ज्यादातर विवाद निपटान तंत्र को पंगु बनाकर, अमेरिका द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन पर विकसित देशों का वर्चस्व रहा है, जिसमें अमेरिका प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अमेरिका अब संरक्षणवादी होता जा रहा है, व्यापार और निवेश उदारीकरण का समर्थन करने के अपने पहले के रुख से हटकर, टैरिफ में कटौती पर जोर दे रहा है। 'अमेरिका फर्स्ट' के लक्ष्य को साकार करने के लिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको के साथ उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत की है। इसके विपरीत, चीन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार के समर्थक के रूप में उभरा है क्योंकि यह दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है।

इस संदर्भ में, भारत के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपने व्यापार और आर्थिक संबंधों का विस्तार करे और निर्यात बाजार बनने के उद्देश्य से भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनने पर ध्यान केंद्रित करे।

15.5 भारत बनाम आसियान

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम शामिल हैं। उदारीकरण के बाद से आसियान के साथ एक मजबूत और बहुआयामी संबंधों पर भारत का ध्यान और

आर्थिक स्थान के लिए इसकी निरंतर खोज के परिणामस्वरूप 'पूर्व की ओर देखो' नीति बनी। यह आज एक गतिशील और कार्रवाई उन्मुख 'एक्ट ईस्ट' नीति में परिपक्व हो गया है। नवंबर 2014 में म्यांमार के ने पी ताव में आयोजित 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से 'एक्ट ईस्ट' नीति की घोषणा की।

अपनी भागीदारी को तेज करने के लिए आसियान और भारत के हित के प्रतिबिंब के रूप में, शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए आसियान–भारत साझेदारी, जो दीर्घकालिक आसियान–भारत जुड़ाव के लिए रोडमैप निर्धारित करती है, पर 2004 में वियनतियाने में तीसरे आसियान–भारत शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार के अनुसार, साझेदारी को लागू करने के लिए 2004–2010 की अवधि के लिए एक कार्य योजना (POA) भी विकसित की गई थी। तीसरा पीओए (2016–20) अगस्त 2015 में आयोजित आसियान–भारत विदेश मंत्रियों की बैठक द्वारा अपनाया गया था। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अलावा, आसियान और भारत ने 2016–2018 की अवधि के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है और पहले से ही इसके तहत गतिविधियों को लागू कर रहे हैं, जो 2016–2020 की कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन की दिशा में योगदान देगा।

भारत–आसियान व्यापार और निवेश संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान के साथ भारत का व्यापार 81.33 अरब डॉलर है, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6 प्रतिशत है। मंत्रालय का कहना है कि आसियान को भारत का निर्यात हमारे कुल निर्यात का 11.28 प्रतिशत है। अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध को तेज करने की पृष्ठभूमि में, इसे बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग के लिए मुख्य धक्का कारक माना जाता है।

हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान सामूहिक रूप से इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में नियम–आधारित व्यवस्था को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र के मजबूत समर्थन में सामने आए हैं, जहां चीन अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स कर रहा है। चारों देशों ने आसियान की केंद्रीयता और आसियान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय वास्तुकला के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। 10–राष्ट्र संघ को इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है और भारत और कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं।

15.6 भारत और जी20

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित नीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से 1999 में स्थापित जी20, आर्थिक और वित्तीय संबंधों और नीति के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय पर लक्षित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पहल की एक श्रृंखला में नवीनतम है। इसके साथ शुरू करने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) शामिल था, जिसे बाद में विश्व बैंक के रूप में फिर से नाम दिया गया। इसने तब से विश्व व्यापार संगठन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

जी20 सदस्यता में दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण शामिल है, जो दुनिया की आबादी का लगभग दो–तिहाई, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का

85 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ हैं। .

भारत जी20 के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उभरा है – जो विश्व आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को फिर से आकार देने में योगदान और प्रभावित कर रहा है। भारत जी20 के लिए एक महत्वाकांक्षी बहु–आयामी एजेंडा का अनुसरण कर रहा हैः बुनियादी ढांचे के विकास, समावेशी विकास, ऊर्जा दक्षता से लेकर आतंकवाद को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई, वैश्विक वित्तीय वास्तुकला में सुधार, भ्रष्टाचार और काले धन के लिए वैश्विक अधिशेष को तैनात करने से लेकर। भारत का मुख्य एजेंडा रोजगार सृजन, स्थिर वित्तीय बाजारों और वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए स्थिर और सतत वैश्विक विकास के आसपास केंद्रित है। तदनुसार, देश व्यापार और निवेश के अलावा गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर जोर दे रहा है।

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों के प्रमुखों ने जून 2019 के दौरान ओसाका, जापान में हाल ही में जी20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात की, ताकि प्रमुख वैश्विक आर्थिक चिंताओं को दूर किया जा सके और सामाजिक मुद्दों से निपटकर समावेशी और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां। जी20 में भारत के शेरपा सुरेश प्रभु ने ओसाका में शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कर चोरी, आर्थिक अपराधों और भगोड़े अपराधियों (देश से) पर काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक समुदाय को आर्थिक अपराध करने वाले और भागने वाले लोगों के मुद्दों से निपटने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। प्रभु ने यह भी कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और देश बिजली पैदा करने के लिए स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

जी20 स्थिति रिपोर्ट में जी20 में भारत के निम्नलिखित प्रयासों की सराहना की गई हैः

1. एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत ने अच्छा काम किया है;
2. अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने देखा कि श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत ने श्रम सुधारों में अच्छा काम किया है; तथा,
3. भारत ने नवोन्मेष को बढ़ावा देकर और व्यापार करना आसान बनाकर बाहरी उधारी की सुविधा के लिए स्टार्ट–अप की शुरुआत की है।

बोध प्रश्न 2

1. भारत ने विश्व व्यापार संगठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। व्याख्या कीजिये.
2. बताएं कि भारत ने आसियान देशों में कैसे कदम जमाया.
3. भारत किस प्रकार G20 का लाभ उठा रहा है?

.....

.....

.....

.....

.....

15.7 दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार संबंध

सितंबर 2018 को जारी 'ए ग्लास हाफ फुलः द प्रॉमिस ऑफ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया ' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में, रिपोर्ट के प्रमुख लेखक और विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री संजय कथूरिया ने कहा विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण एशिया के साथ माल में भारत का संभावित व्यापार 19 बिलियन डॉलर के वास्तविक व्यापार के मुकाबले 62 बिलियन डॉलर है। यह वैश्विक व्यापार का महज 3 फीसदी है और इसकी क्षमता से करीब 43 अरब डॉलर कम है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में, गहन व्यापार सहयोग की दिशा में एक वृद्धिशील दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली हो सकता है और इस क्षेत्र ने भारत–श्रीलंका हवाई सेवा उदारीकरण और भारत–बांग्लादेश सीमा 'हाट' के रूप में इसके उदाहरण देखे हैं।

2015 में, शेष विश्व से 510 अरब डॉलर के दक्षिण एशिया में कुल आयात, 329 अरब डॉलर के शेष विश्व को निर्यात और 839 अरब डॉलर के शेष विश्व के साथ कुल व्यापार के साथ, दक्षिण एशिया में विश्व के आयात का 3 प्रतिशत हिस्सा था। ऊपर कहा गया है, विश्व निर्यात का 1.99 प्रतिशत और विश्व व्यापार का 2.5 प्रतिशत। दक्षिण एशिया के भीतर, भारत सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था है। 510 अरब डॉलर के कुल आयात में से, भारत में आयात (क्षेत्र के बाहर से) 391 अरब डॉलर था, जिसमें दक्षिण एशिया में कुल आयात का 77 प्रतिशत हिस्सा था। इसी तरह, 264 बिलियन डॉलर (क्षेत्र के बाहर) के कुल निर्यात के साथ, भारत ने सितंबर 2017 में प्रकाशित वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया से 329 बिलियन डॉलर के कुल निर्यात में 80 प्रतिशत का योगदान दिया।

दक्षिण एशिया और अमेरिका दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। हालाँकि, जबकि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष इस क्षेत्र में भारत के निर्यात का केवल 16 प्रतिशत है, दक्षिण एशिया के साथ भारत का व्यापार अधिशेष, इस क्षेत्र में निर्यात का एक असाधारण 87 प्रतिशत है। यह न केवल दक्षिण एशिया में भारत की वर्तमान प्रमुख स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि अंतर–क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि यदि पड़ोसियों के साथ व्यापार की बाधाओं को हटा दिया जाता है, तो दक्षिण एशिया में अंतर–क्षेत्रीय व्यापार मौजूदा 28 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर हो सकता है। इसलिए, क्षमता की प्राप्ति के लिए ऐसे व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है।

2016–17 के लिए वाणिज्य विभाग के व्यापार आंकड़ों के आधार पर, दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापार की मुख्य विशेषताओं का सारांश नीचे दिया गया हैः

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव हैं.
- दक्षिण एशिया में सबसे अधिक निर्यात बांग्लादेश को भी होता है जिसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव का स्थान आता है।

- दक्षिण एशिया में कुल निर्यात का 83 प्रतिशत बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को किया गया.
- अकेले बांग्लादेश ने निर्यात में 35 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया, नेपाल ने 28 प्रतिशत का योगदान दिया, श्रीलंका ने लगभग 20 प्रतिशत, पाकिस्तान ने लगभग 10 प्रतिशत; अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव को निर्यात कुल मिलाकर दक्षिण एशिया को निर्यात का केवल 7 प्रतिशत था.
- सबसे अधिक आयात बांग्लादेश से होता है जिसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव का स्थान आता है.
- भारत के पास दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ पर्याप्त व्यापार अधिशेष है। निर्यात और आयात की प्रवृत्ति के अनुरूप, व्यापार अधिशेष के मामले में शीर्ष तीन देश बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका हैं.
- निर्यात के अनुपात में व्यापार अधिशेष भूटान और अफगानिस्तान के लिए कम से कम है, जो दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में उनके साथ अधिक संतुलित व्यापार का संकेत देता है।.
- निर्यात के अनुपात के रूप में व्यापार अधिशेष मालदीव के लिए सबसे अधिक है, उसके बाद नेपाल और श्रीलंका का स्थान है, जो उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार में भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है।.

बोध प्रश्न 3

1. भारत दक्षिण एशिया के देशों के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। व्याख्या कीजिये।

.....

.....

.....

.....

.....

15.8 व्यापार और विदेश नीति

सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से दो हैं एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच तेजी से बढ़ता व्यापार युद्ध और दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति की पसंद, जहां भारतीय और अमेरिकी हित टकरा रहे हैं।

एक तरफ ट्रम्प प्रशासन द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी और काउंटर–हाइक के माध्यम से छेड़े गए व्यापार युद्ध, दूसरी ओर, कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से चीन, 2018–19 के दौरान तेज हो गए हैं। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 250 बिलियन डॉलर का टैरिफ लगाया है और बीजिंग ने अमेरिकी निर्यात पर 110 बिलियन डॉलर का जवाबी कार्रवाई की है। कनाडा और

मेक्सिको ने ट्रंप के स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ के जवाब में 20 बिलियन डॉलर और जोड़े हैं।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी बाजार खोलने के लिए टैरिफ एक अल्पकालिक मूल्य है। हालांकि, परेशानी यह है कि अमेरिका के लिए बाजार खोलने की कीमत तेजी से बढ़ रही है और यह सिर्फ अल्पकालिक नहीं हो सकता है। चीन के साथ बातचीत भी ठप है।

नियम–आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था लंबे समय से इस धारणा से पुष्ट हुई है कि आर्थिक उदारीकरण और विकास चीन को वैश्विक व्यापार और निवेश के पश्चिमी शैली के आर्थिक मानदंडों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश करने के बाद से उन मानदंडों को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो क्या यह उम्मीद करना अवास्तविक नहीं होगा कि वह टैरिफ और व्यापार युद्ध के खतरों के तहत अमेरिकी मांगों को शर्मनाक तरीके से स्वीकार करेगा। वैश्विक व्यापार में चल रही समस्याएं कहां खत्म होंगी यह अभी स्पष्ट नहीं है? जिस भी तरीके से व्यापार विवाद समाप्त होता है, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका के लिए अलग–अलग दृष्टिकोणों से देशों के बीच तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है।

यह भारत के लिए भी व्यापार और विदेश नीति की चुनौतियों का सामना करता है। 1 अक्टूबर 2018 को, राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत को ''टैरिफ किंग'' करार दिया और अपने आरोपों को दोहराया कि नई दिल्ली ने विभिन्न अमेरिकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ दरों का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय उत्पादों के आयात पर समान शुल्क लगाने के खिलाफ चेतावनी देने के बाद, भारतीय वार्ताकारों ने उन्हें फोन किया कि वे अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता करना चाहते हैं। "हमारे पास एक देश है, भारत को ले लो। अच्छा संबंध। वे अब एक सौदा करना चाहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि मैं वह करूं जो मैं करने जा रहा हूं, जो मुझे करना है। इसलिए, वे (भारतीय) हमें बुलाते हैं। वे किसी और के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे,'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था।

ट्रम्प ने यह धारणा बनाने की कोशिश की है कि भारत अमेरिकी कार्रवाई की धमकी के तहत मुड़ा हुआ है। ट्रंप अक्सर भारत पर अमेरिकी उत्पादों पर 100 फीसदी शुल्क लगाने का आरोप लगाते रहे हैं। एक महीने पहले उन्होंने कहा था कि भारत इस मुद्दे पर उनके प्रशासन के सख्त रुख के बावजूद अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हर बार भारत के साथ व्यापार संबंधों पर टिप्पणी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा मैत्रीपूर्ण से बहुत दूर है। लेकिन फिर, भारत शायद ही यहां उच्च नैतिक आधार का दावा कर सकता है। करीब से निरीक्षण करने पर, यह पाया जा सकता है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक संरक्षित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ब्रिक्स के सदस्यों में– ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका–भारत में खाद्य पदार्थों, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक आदानों पर सबसे अधिक प्रभावी टैरिफ दरें हैं।

जून 2018 में, ट्रम्प प्रशासन द्वारा कुछ भारतीय सामानों पर उच्च टैरिफ लगाए जाने के बाद, भारत ने अमेरिका से आयात किए गए कृषि, लौह और इस्पात उत्पादों की एक श्रृंखला पर शुल्क में वृद्धि की थी, जो कि एक जैसे तो तैसा कदम था। सितंबर में, भारत ने फिर से 18 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया और जेट ईंधन पर एक नया कर पेश किया क्योंकि यह

अपने चालू खाते के घाटे को कम करना चाहता है, जिसका वजन रुपये पर पड़ा है। इन सभी ने अमेरिकी प्रशासन को ताजा गोला–बारूद दिया।

भारत की अपनी संरक्षणवादी नीतियों को देखते हुए, एक पूर्ण विकसित भारत–अमेरिका व्यापार युद्ध की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता था। अब तक, भारत की अर्थव्यवस्था एक सुस्त निर्यात बाजार से प्रभावित थी, क्योंकि वैश्विक व्यापार युद्ध में होने वाले बदलावों के बारे में आशंकाओं के कारण। लेकिन अगर भारत सीधे तौर पर इसमें उलझा हुआ है, तो यह घरेलू उद्योग, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, परिधान और वस्त्र, लोहा और इस्पात, खनिज ईंधन और मत्स्य पालन के लिए विनाशकारी हो सकता है। निर्यात मांग में मंदी और विदेशी निवेश के बहिर्वाह से चालू खाता घाटा (CAD) पर और दबाव पड़ने की संभावना है।

जून 2018 में व्यापार और निवेश पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2018 के अनुसार, इस समय के दौरान पूंजी बहिर्वाह और एफडीआई मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। यूएस फेड द्वारा मात्रात्मक सहजता के कारण जो पैसा उपलब्ध था, वह सूख रहा है, क्योंकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को कड़ा करने की स्थिति में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में एफडीआई बहिर्वाह दोगुने से अधिक बढ़कर 11.3 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि एफडीआई प्रवाह 9 फीसदी गिरकर 40 बिलियन डॉलर हो गया। व्यापार समस्याओं के प्रभाव की तुलना में पूंजी प्रवाह के कारण रुपया अधिक कमजोर होगा.

भारत ईरान से कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक (चीन के बाद) है, जिसके तेल व्यापार पर 2015 में संपन्न परमाणु समझौते से ट्रम्प प्रशासन की एकतरफा वापसी के बाद 4 नवंबर 2018 से अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लगाए गए थे। ईरान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध हैं सिर्फ तेल केंद्रित नहीं वे तेल को लंबी अवधि के रणनीतिक जुड़ाव से आगे बढ़ाते हैं। भारत ने अफगानिस्तान, मध्य एशिया और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारे के लिए एक ट्रांजिट हब के रूप में ईरान के चाहबार बंदरगाह के विकास में निवेश किया है। भारत ईरान में दो गैस फील्ड फरजाद–बी और साउथ पार विकसित कर रहा है। दोनों देश अफगानिस्तान संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों में सहयोग करते हैं।

राष्ट्रीय आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुरक्षित करने के लिए तैयार की गई व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों में भारत के लिए एक सबक है। वार्ता का रास्ता न अपनाकर, भारत ने अनजाने में संरक्षणवाद की बहस में एक नया मोर्चा खोल दिया हो सकता है, उदाहरण के लिए, डेटा पर जो कई लोग कहते हैं कि नया तेल है।

भारत रूस और ईरान जैसे कच्चे तेल उत्पादक देशों के साथ रुपये और वस्तु विनिमय आधारित व्यापार समझौतों की व्यवहार्यता की खोज कर रहा है। तेजी से कठोर अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध नीति के बीच रूस कई देशों में से एक था जो डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता था। ईरान उपायों के एक पैकेज के माध्यम से अपने व्यापार के लिए डॉलर को अप्रासंगिक बनाने के प्रयास भी कर रहा था, जिसमंह यूरो और अन्य मुद्राओं का उपयोग करके व्यापार में वृद्धि शामिल थी।

एक महत्वपूर्ण कारक जिसने चीन–अमेरिकी व्यापार घर्षण को जन्म दिया, वह यह था कि प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, चीन अपनी 'मेड इन चाइना 2025' रणनीति को आगे बढ़ा रहा है,

जिसका लक्ष्य इसे उन क्षेत्रों में ड्राइविंग सीट पर स्थापित करना है, जिन्हें उसके नेताओं ने आवश्यक समझा है। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने इस रणनीति के जबरदस्ती आवेदन में गलती की है – यह अक्सर एक झटके के रूप में होता है क्योंकि देश ने विदेशी कंपनियों को चीन के आकर्षक बाजारों तक पहुंच के बदले में अपनी तकनीक सौंपने के लिए मजबूर किया है।

विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उपयोग करते हुए चीन ने पिछले दो दशकों के दौरान भारतीय बाजारों पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। चीन के साथ व्यापार 1997–98 में 1 बिलियन डॉलर से कम से ज्यादा होकर 2017–18 में 89.71 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत ही नहीं; चीन अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों समेत कई देशों में तबाही मचा रहा है। वास्तव में, चीन का लगभग 130 देशों के साथ व्यापार अधिशेष है। इस वजह से, भारत, अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों में उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इससे इन सभी देशों में भारी बेरोजगारी पैदा हो गई है।

15.9 भारत 2030

2030 में, 1.5 बिलियन की आबादी और 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ, भारत की प्रति व्यक्ति आय 6,600 डॉलर होगी (आज चीन 9,000 डॉलर और थाईलैंड 6,000 डॉलर की तुलना में 2,000 डॉलर से)। अगर हम सालाना 7 प्रतिशत की दर से विकास करना जारी रखते हैं, तो भी प्रति व्यक्ति आय आज से 20 साल बाद भी चीन की तुलना में कम होगी।

2030 तक भारत की 50 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। भारत के शीर्ष 5 शहरों की अर्थव्यवस्था की तुलना आज के मध्यम आय वाले देशों से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, मैकिन्से की एक रिपोर्ट, भारत की चढ़ाई – विकास और परिवर्तन के लिए पांच अवसर, के अनुसार 2030 में मुंबई की अर्थव्यवस्था, अनुमानित 245 बिलियन डॉलर, आज मलेशिया की तुलना में बड़ी होगी। विदेश व्यापार नीति (2015–20) से प्रेरित होकर, भारत का निर्यात 2019 तक 750 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2020 तक 3 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से दोगुनी होने की उम्मीद है (विश्व बैंक के अनुमान और फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया) भारतीय निर्यात संगठन–फियो अनुमान)।

भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार, कुल एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2014 में 45.15 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 18 में 61.96 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत कई व्यावसायिक अवसरों और अनुकूल नीतियों की भी पेशकश कर रहा है, जो सभी क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमेजन ने आने वाले 5 वर्षों में 5 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वचन दिया है; दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर रिटेलर IKEA ने 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई हैय IFC, विश्व बैंक की निवेश शाखा, 2022 तक कई टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में 6 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भारत में विनिर्माण आधार स्थापित कर रहे हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि भारत विदेशी खिलाड़ियों के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बन रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र में, भारत उच्च स्तर की कनेक्टिविटी और डेटा की समृद्धि के साथ उद्योग 4.0 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डमपजल), भारत सरकार के अनुसार, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सामान उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और 2020 तक 400 बिलियन डॉलर का होने की उम्मीद है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक है, जिसके पास 2014 में 2 इकाइयों की तुलना में 120 मोबाइल निर्माण इकाइयां हैं।

नई औद्योगिक नीति 27 साल पुरानी मौजूदा नीति का स्थान लेगी और बुनियादी ढांचे, श्रम कानूनों और कारोबारी माहौल के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करेगी। इस नीति का लक्ष्य सालाना 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना है और यह मेक इन इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत हिस्सा वर्तमान में 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 मिलियन नई नौकरियां पैदा करना है।

बोध प्रश्न 4

1. यूएस के साथ टैरिफ संबंधी समस्याओं की व्याख्या करें.
2. क्या भारत में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है ?

.....

.....

.....

.....

.....

15.10 सारांश

एक एकीकृत दुनिया में, एक देश की आर्थिक नीतियां आमतौर पर अन्य देशों को भी प्रभावित करती हैं। भारत के आर्थिक उदारीकरण की नीति को 1991 से लागू किया गया था। आर्थिक उदारीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू विदेशी व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण, विनियंत्रण, गैर–लाइसेंसिंग, टैरिफ बाधाओं को हटाने, विदेशी निवेश की सुविधा, विनिर्माण को बढ़ावा देना था। निर्यात और रोजगार सृजन पर फोकस के साथ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्ट–अप इंडिया, श्रम कानूनों में बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, औद्योगिक नीति में सुधार, नोटबंदी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) 2030 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को उच्च विकास पथ पर लाने के कुछ ही कदम हैं। . कहने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 ने 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लिया है।

15.11 कुछ उपयोगी संदर्भ

आसियान–भारत, https://mea.gov.in/aseanindia/20–years-html 3 जुलाई 2019 को एक्सेस किया गया

चंद्रशेखर, सी.पी., 1998. ''एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इंडस्ट्री।'' आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 23 (45/47), नवंबर.

दत्त, रुद्र और के.पी. सुंदरम, 2011. भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्लीः एस चंद एंड कंपनी.

वित्त मंत्रालय, आरबीआई सुचारू भारत–ईरान व्यापार सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार कर रहा हैः वाणिज्य सचिव, इकोनॉमिक टाइम्स, 25 सितंबर 2018ः यहां उपलब्धः https://Economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/finance-ministry.आरबीआई–वर्किंग–आउट–मैकेनिज्म–टू– सुनिश्चित–स्मूथ–इंडिया–ईरान–ट्रेड–कॉमर्ससेक्रेटरी/आर्टिकलशो/65953168.cms\utm_source (contentofinterest-utm_medium(text-utm_ campaign) cppst. 1 जुलाई 2019 को एक्सेस किया गया।

G20 शिखर सम्मेलनः भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई की जोरदार वकालत की, मिंट, 30 जून 2019। https://www.livemint.com/news/india/g20-summit-india-pitches-strongly-for-fight- खिलाफ उपलब्ध।–भगोड़ा–आर्थिक–अपराधी–1561806485004.html 1 जुलाई 2019 को एक्सेस किया गया।

गुप्ता, के.एल. और हरविंदर कौर, 2004। नई भारतीय अर्थव्यवस्था और सुधार नई दिल्लीः दीप और दीप प्रकाशन.

गुप्ता, आर.सी. 1973. ''नेहरू की आर्थिक नीति और भारत के लिए इसकी उपयुक्तताः एक मूल्यांकन,'' नेहरू और भारत में योजना में, एन बी दास गुप्ता और अन्य। नई दिल्लीः अवधारणा प्रकाशन।

2016–17 में दक्षिण एशिया के साथ भारत का व्यापार, एक विश्लेषण, वाणिज्य विभाग, एफटी–दक्षिण एशिया डिवीजन, भारत सरकार, सितंबर 2017.

2016 के बाद से ईरान से भारतीय तेल का आयात सबसे अधिक हुआ, रॉयटर्स, 12 जून 2018। यहां उपलब्धः https://in.reuters.com/article/india-oil/indian-oil-imports-from-iran-surge-to- उच्चतम–2016 के बाद से–idINKBN1J81W7. 30 जून 2019 को एक्सेस किया गया.

जैन टी.आर., मुकेश त्रेहन और रंजू त्रेहन, 2009. बिजनेस एनवायरनमेंट, नई दिल्लीः वी.के एंटरप्राइजेज.

कपूर, जे.सी. 1978. वर्ल्ड अफेयर, कपूर सूर्य फाउंडेशन, खंड 2, अप्रैल–जून.

कोठारी, मोनिका, 2007। भारत में निर्यात प्रोत्साहन उपाय। नई दिल्लीः डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स लिमिटेड।

कोचर, समीर और रोहन कोचर, सं. 2019। भारत 2030ः एक सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य, नई दिल्लीः स्कोच मीडिया।

क्रुगमैन, पॉल आर., 2003. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को।

नटराज, गीतांजलि, भारत और जी20ः भारत कैसे विश्व आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को फिर से आकार दे सकता है, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशना, अगस्त 2016।https://www.brookings.edu/opinions/india-and-g20-how-india–बंद– पर उपलब्ध है। नई आकृति–विश्व–आर्थिक–और–वित्तीय–आदेश/. 3 जुलाई 2019 को एक्सेस किया गया।

सेन, कुणाल, 2009। भारतीय विनिर्माण में व्यापार नीति असमानता और प्रदर्शन, यूएसएः रूटलेज।

पंचमुखी, वादीराज राघवेंद्राचार्य, 1978। भारत की व्यापार नीतियांः एक मात्रात्मक विश्लेषण, दिल्लीः नौरंग राय प्रकाशन.

ट्रम्प का कहना है कि 'टैरिफ किंग' भारत उन्हें खुश रखने के लिए व्यापार सौदा चाहता है, ब्लूमबर्ग क्विंट, 2 अक्टूबर 2018। यहां उपलब्धः https://www.bloombergquint.com/global-Economics/trump-says-india-wants-trade-deal-साथ–अमेरिका–मुख्य रूप से रखने के लिए–उसे–खुश। 30 जून 2019 को एक्सेस किया गया।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2018, अंकटाड। देखोः https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspxpublicationid-2130

15.12 आपके प्रगति अभ्यासों की जांच के लिए उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपका उत्तर खंड 15.3 पर आधारित होना चाहिए

2) आपका उत्तर खंड 15.3 पर आधारित होना चाहिए

बोध प्रश्न 2

1) आपका उत्तर खंड 15.4 पर आधारित होना चाहिए

2) आपका उत्तर खंड 15.5 पर आधारित होना चाहिए

3) आपका उत्तर खंड 15.6 पर आधारित होना चाहिए

बोध प्रश्न 3

1) आपका उत्तर खंड 15.7 पर आधारित होना चाहिए

बोध प्रश्न 4

1) आपका उत्तर खंड 15.9 पर आधारित होना चाहिए

2) आपका उत्तर खंड 15.9 पर आधारित होना चाहिए